★सुरक्षा★विकास★जागरण★एकता

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच

Forum for Awareness of National Security (FANS)
(Regd. No. S/1723/District South/2014)
101, H.I.G. DDA Flats, Block-1,
Motia Khan, Paharganj Pin Code. 110055.
M: 8178828297, 8375965010 Ph: 011-43524524

प्रस्ताव क्र-.1

एशियाई क्षेत्र में चीन की धौंस-पट्टी

भारत और चीन के क्रमश: 1947 और 1949 में स्वतंत्र होने से पहले दोनों देशों के बीच सदियों से बहुत सौहार्दपूर्ण और मधुरसंबंध थे।भारत द्वारा श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद, मसलनपंचशील के सिद्धांत, चीन समेतबाकी दुनिया के साथशांतिपूर्ण सह अस्तित्व आदि जहां चीन भी एक हस्ताक्षरकर्ता था, इन सबके बाद भी भारत और चीन के बीच संबंध बिगड़ने लगे। साल 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जा करने के बाद भारत के साथ उसकी शत्रुता बढ़तीही गई। ज्ञात हो कि तिब्बत एक स्वायत्त निकाय था और कभी चीन का हिस्सा नहीं रहाथा।इसके बाद भारत ने धार्मिक नेता दलाई लामा सहित हजारों तिब्बतियों को शरण दी, जो चीन के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से बचकर साल 1959 में भागकर भारत आए।

चीन ने भारत के साथ सीमा मुद्दे हल नहीं किए।भारत और चीन के बीच सीमा के रूप में मैकमोहन लाइन को स्वीकार करने के बजाय चीन ने भारत के अभिन्न अंगों लद्दाख,भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल परदावा करना शुरू कर दिया।यह चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति मात्से तुंग का विचार था, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि उसनेतिब्बत को पहले ही जोड़ लिया है, जिन्हें वह हाथ की हथेली मान रहा था और उपरोक्त वर्णित पांच राज्यों कोपांच अंगुलियों के सरीखा मान रहा था। इन सभी पर कब्जा करने को लेकर उसकी निगाहें थी। चीन ने 1962 में बिना किसी उकसावे के भारत पर हमला कर दिया और हमारी सीमा में लद्दाख सेक्टर के 40,000 वर्गकिलोमीटर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक भू-भाग पर दावा जताने लगा।

फिरचीन ने पाकिस्तान के साथ मिलीभगत करके पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जोकि पाकिस्तान द्वारा अवैध तौर पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद चीन ने कराची के ग्वादर बंदरगाह से अपने देश के साथ जोड़ती हुई सड़क का निर्माण शुरू कर दिया (जिसे पाकिस्तान पहले ही चीन को बतौरउपहार दे चुका है), यह सड़क गिलगिट-बाल्तिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और बेशक पाकिस्तान से होकर निकल रही है। पाकिस्तान नेगिलगिट-बाल्तिस्तान को अवैध तरीके से अपने पांचवे प्रांत के रूप में घोषित करने की योजना बनाई, जिसकीब्रिटेन सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की। चीन ने म्यांमार,बांग्लादेश में चटगांव, श्रीलंका के हंबनटोटा और कराची के ग्वादर में बंदरगाह का निर्माण करकेभारत कोसमुद्री मार्गों के जरिये पहले ही घेर लिया है। यह भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा और चिंता का विषय है।

समय-समय पर चीन हमारे सीमा क्षेत्रों का उल्लंघन करता है, कभी हमारे भू-भाग में घुसपैठ करके तो कभी वायुसीमा का उल्लंघन करके। हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करके हमें उकसावे की कार्रवाई से भी बाज नहीं आता है,जो पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है।चीन ने जम्मू-कश्मीर के निवासियों और अरुणाचल प्रदेश के बाशिंदों को पेपर वीजा जारी करना शुरू कर दिया।भारत के अंदर होने वाले बौद्ध सम्मेलनों में भाग लेने के लिएराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे बड़ी शख्सियतों की आवाजाही पर भी चीन समय समय पर आपत्ति जताता रहता है। अरुणाचल प्रदेशऔर भारत के अंदरअन्य स्थानों पर तिब्बतियों के धार्मिक नेता दलाई लामा की आवाजाही पर भी चीन विरोध करता है। अभी हाल में चीन ने दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, भारत ने इन विरोधों और खतरों को नजरअंदाज किया और दलाई लामा धार्मिक गतिविधियों के लिए अरुणाचल प्रदेश गए।

परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार को लेकर सभी मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की खिलाफत करते हुए चीन ने पाकिस्तान को उसके परमाणु कार्यक्रम में सहायता की और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसाने का भी काम किया। यही नहीं, चीन लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता

कोअवरुद्ध कर रहा है जबकि भारत ने सभी कूटनीतिकसिद्धांतों और मानदंडों को परे रखकर अत्यधिक उदारता का परिचय देते हुए चीन को इसकी सदस्यता दिए जाने की पेशकश की थी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने पाकिस्तान के अजहर मसूद कीआतंकवादी गतिविधियों की निंदा की और उसे आतंकी घोषित किया, लेकिन चीन इस आतंकी के पक्ष में लगातार वीटो का इस्तेमाल करता रहा और इस आतंकी पर प्रतिबंध की घोषणा में बाधाएं खड़ी करता रहा। हालांकि, चीन के दोहरे रवैये से भारत भलीभांति वाकिफ है। पूर्व में कई ऐसे मामले सामने आए जिससे चीन की चालबाजियां सामने आईं। चीन हमेशा धौंस जमाकर एशियाई क्षेत्र में असंतुलन बनाने की कोशिश में लगा रहता है। यहां तक कि पूर्व में अमेरिका भीएशियाईक्षेत्र में चीन के क्षेत्रीय विस्तारवादके खिलाफ कड़ी चिंता जाहिर कर चुका है।

संकल्प प्रस्तावना:

फैन्स दृढ़ता के साथ चीन की चालाबाजियां, आधिपत्य भरे रवैये और अस्वीकार्य कारनामों की कड़ी निंदा और विरोध करता है, जोकि खुद उसकी सुरक्षा एवं अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही, राजनयिक स्तर पर शांतिपूर्ण वार्ता की हिमायत करते हुए राष्ट्र की संप्रभुता को किसी भी कीमत पर बचाने का संकल्प लेता है।